श्री म० ला० सोंधी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हेम बरुआ :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री मो० व० मसानी :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में हाल में भरवों के समर्थन में किये गये प्रदर्शन के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की जीप एवं गिरजाघरों को पहुंचाई गई क्षति के बारे में जांच करवाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) भारत सरकार ने इस विषय में कोई जांच नहीं करवाई है । संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक दल की किसी जीप को क्षति पहुंचने के बारे में कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

National Laboratories

3887. Shri Nitiraj Singh Chaudhary:
Shri G. S. Mishra:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 1646 on the 7th June, 1967 and state:

(a) the amount spent on establishment, buildings and research separately, for each Laboratory during the last three years;

1019 (Ai) LSD—5.

(b) whether any proposal of establishing more National Laboratories is under consideration of Government; and

(c) if so, where and when?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Three statements showing the amount spent on establishment, buildings and research during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-832/67].

(b) At present there is no such proposal under consideration.

(c) Does not arise.

लोक पाल/लोक आयुक्त

3888. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री शालिग्राम दास :
श्री नरदेव स्नातक :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह मंत्रियों की त्रुटियों की जांच के लिये लोक पाल तथा लोक आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में, लोक-शिकायत निवारण की समस्या पर दी गई सिफारिशों पर अपने विचार भेजे हैं, जो विचाराधीन हैं ।